रविवारीय

बांग्लादेश, भारत को दे रहा है कूटनीतिक धोखा

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

किसी भी देश को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार होता है, लेकिन जब कोई पड़ोसी राष्ट्र ऐसे संकेत देने लगे कि वह अपने सबसे बड़े सहयोगी और निकटतम साझेदार की चिंताओं तथा हितों की अनदेखी कर रहा है,तब स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़ जाती है. भारत और बांग्लादेश के बीच साझा इतिहास,सांस्कृतिक निकटता,भौगोलिक परस्पर निर्भरता और आर्थिक सहयोग का एक मजबूत आधार मौजूद है. भारत ने विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश के विकास,परियोजनाओं,ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. ऐसे में यदि ढाका की कूटनीति भारत जैसे सहयोगी की अपेक्षाओं और संवेदनशीलताओं से दूरी बनाती हुई दिखाई देती है, तो नई दिल्ली के लिए चिंता स्वाभाविक है. खास तौर पर जब यह दूरी उन देशों के साथ बढ़ती निकटता के रूप में दिखाई दे,जिनके साथ भारत के संबंध बहुत जटिल और चुनौतीपूर्ण हो.

तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में नई सरकार बनी,तब यह उम्मीद की जा रही थी कि दोनों देशों के रिश्तों में आई दूरी कम होगी और पारंपरिक सहयोग की भावना को नया बल मिलेगा. लेकिन सत्ता संभालने के बाद उनके कुछ कदमों ने भारत की चिंताओं को कम करने के बजाय बढ़ा दिया है. चीन के साथ बढ़ती सक्रियता,पाकिस्तान के साथ संबंधों में तेजी से सुधार,बांग्लादेशी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान को प्राथमिकता देना तथा रक्षा सहयोग के नए संकेत ऐसे घटनाक्रम हैं जिसने नई दिल्ली की चिंताओं को निश्चित ही बढ़ा दिया है.

> साझा इतिहास,भाषा, संस्कृति और 1971 के मुक्ति संग्राम की स्मृतियों ने भारत और बांग्लादेश को एक-दूसरे के निकट रखा है,लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं जो समय-समय पर रिश्तों में तनाव और अविश्वास पैदा करते रहे हैं. तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर बांग्लादेश लंबे समय से समझौते की मांग कर रहा है. चार हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा प्रबंधन से जुड़े प्रश्न दोनों देशों के लिए लगातार चुनौती बने हुए है. भारत की सुरक्षा चिंताओं और बांग्लादेश की राजनीतिक संवेदनशीलताओं के बीच संतुलन स्थापित करना आसान नहीं रहा है. अवैध प्रवास का मुद्दा लंबे समय से भारत की आंतरिक राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा बहस का हिस्सा रहा है. अनियंत्रित और अवैध सीमा पार आवाजाही से आपराधिक गतिविधियों और तस्करी नेटवर्क भारत के लिए संकट बढ़ाता रहा है,यह संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर दबाव का मुद्दा भी है. सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि,पहचान संबंधी विवाद तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े प्रश्न बहुत जटिल है.

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम प्रशासन के प्रमुख रहे मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पहल की थी. अब तारिक रहमान की सरकार उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है. ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानों की बहाली,उच्चस्तरीय राजनयिक संपर्कों में वृद्धि तथा रक्षा सहयोग पर चर्चाएं इसी बदलती नीति के संकेत हैं. बांग्लादेश पाकिस्तान के जेएफ-17 लड़ाकू विमान खरीदने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है. यदि ऐसा होता है तो यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं होगा,बल्कि दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी माना जाएगा. 1971 के बाद दोनों देशों के संबंध लंबे समय तक सीमित रहे थे,लेकिन अब दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संपर्क बढ़े हैं. ऐसे में जेएफ-17 की खरीद इस बात का संकेत मानी जा सकती है कि ढाका इस्लामाबाद के साथ दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी विकसित करना चाहता है. जेएफ-17 विमान पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजना है. इसलिए यह सौदा केवल पाकिस्तान से जुड़ा मामला नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश की रक्षा संरचना में चीन की तकनीकी और रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करेगा. भारत पहले से ही अपने उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे में पूर्वी क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान से जुड़े रक्षा सहयोग का विस्तार भारत की रणनीतिक तैयारियों को प्रभावित कर सकता है.

भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल बंटवारा लंबे समय से द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है. चीन ने इस मुद्दे में अपनी रुचि दिखाई है. बीते वर्षों में चीन ने तीस्ता नदी के प्रबंधन,जल संरक्षण और नदी तट विकास से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश की इच्छा व्यक्त की थी. चीन का यह सहयोग दक्षिण एशिया में उसके बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के रूप में दिखाई देता है.

भारत को लेकर चीन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करना माना जाता है. बांग्लादेश का महत्व उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण बढ़ जाता है. भारत के पूर्वी पड़ोस में स्थित बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी तक पहुंच प्रदान करता है और उत्तर-पूर्व भारत के निकट होने के कारण भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यही कारण है कि चीन ने पिछले डेढ़ दशक में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश, अवसंरचना निर्माण और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया है. बंदरगाहों,पुलों,राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में चीनी निवेश लगातार बढ़ा है. चीन आज बांग्लादेश के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों और रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है. बांग्लादेशी सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे अनेक सैन्य उपकरण चीनी मूल के हैं और रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है. यदि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करता है और चीन की भागीदारी यहां बढ़ती है तो भारत के लिए लड़ाई का तीसरा मोर्चा खुल सकता है.

तारिक रहमान ने जब इस साल फरवरी में चुनाव के बाद बांग्लादेश की सत्ता की कमान संभाली थी,उसी समय पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया था. लेकिन बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पहले विदेश दौरे के लिए चीन जाने वाले हैं. तारिक रहमान,नदी प्रबंधन और जल परियोजनाओं में चीन की अधिक भागीदारी बढ़ाना चाहते है और यह स्थिति भारत को असहज करने वाली होगी. भारत को यह आशंका है कि इसके जरिए चीन भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी आर्थिक और तकनीकी उपस्थिति मजबूत कर सकता है.

व्यंग्य

सूट बूट वाला तिलचट्टा...!

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

हमारी डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि अब इसमें छिपकलियां और कॉकरोच तक इंट्रेस्ट लेने लगे हैं. यह हमारी डेमोक्रेसी के समावेशी (इन्क्लूसिव) होने का एक बहुत बड़ा सबूत है. अमेरिका जब से ईरान सहित अन्य देशों के साथ युद्ध में अपने मुंह की खाने लगा है तब से मेड इन यूएस तिलचट्टा (कॉकरोच) वहां से निकल निकल कर देश की सियासत में शामिल होने के लिए हमारे यहां पहुंचने लगे हैं. दोस्तों सन् 2026 में भारत में व्हाया अमेरिका कॉकरोच जनता पार्टी (डिजिटल) लांच हुई है . मजेदार बात यह है कि इस लांचिंग का देश के विपक्ष ने खुली बाहों से स्वागत किया है. भला इतना सौहार्द की पॉलिटिक्स दुनियां के किसी देश में देखा है क्या. नहीं ना. तभी तो देश को अजूबों का देश कहा जाता है. सुटेड- बूटेड तिलचट्टे को देख कर फक्र होता है कि यहां के तिलचट्टे का वहां किस तरह मेक ओवर हो जाता है. यहां का हरीलाल फॉरेन जा कर कैसे हैरी बन जाता है. बता दें कि हमारे यहां तिलचट्टे या कॉकरोच का स्वागत या तो चप्पल से किया जाता है या लक्ष्मण रेखा या रेड हिट से. यह महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और कई बीमारियों की जड़ है. आजादी की लड़ाई के समय और उसके बाद देश की सियासत में नेताओं द्वारा टोपियां पहनी जातीं थीं. बाद में यह टोपी जनता को पहनाई जाने लगीं.उन टोपियों के रंग भले ही अलग अलग हों, पर उन सब का लक्ष्य एक ही होता है,जन सेवा के नाम पर अपने कुटुंब की सेवा. उसमें देश भक्ति लुप्त होती है. उसका जिम्मा ख़ाकी यूनिफॉर्म के पास है. देश भक्ति और जन सेवा का काम उन्हीं के जिम्मे है.

पहले टोपी,नेता की पहचान हुआ करती थी. पर जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र जवान होता गया,नेताओं की नीयत और जमाना बदला और नेताओं ने जनता को ही टोपी पहनाना शुरू कर दिया.तब से सोसाइटी में टोपी की इज्जत घटती चली गई और उसके साथ नेताओं के सिर से टोपियां भी गायब होती चली गईं. अब उन्हीं के सिर पर टोपियां शोभायमान हैं जिन के मस्तक से केश नदारद हो गए हैं. वैसे भी मस्तक की शोभा केशों से ही होती है. लेकिन आज के जमाने में आदमी की इज्जत केश से नहीं कैश से होती है. जितना कैश उतना ऐश. नेताओं ने इस मर्म को भली भांति समझा है. पहले चंदा विनम्रता और अनुरोध पूर्वक मांगा जाता था. अब अल्टीमेटम होता है. हमारे नेताओं और लोकतंत्र के साथ अब हमारा समाज और जमाना भी मॉर्डन हो गया है. अब वो जमाना गुजर गया जब राजनैतिक दलों के चुनाव निशान समाज से जुड़े होते थे. बैलजोड़ी, गाय- बछड़ा, दीपक, शेर, हाथी हंसिया और धान की बाल या हंसिया और हथौड़ा, वट वृक्ष या झोपड़ी हुआ करता था.निर्वाचन आयोग ने अब पशु संरक्षण के नाम पर जानवरों के चुनाव निशान देना बंद कर दिया और झोपड़ी की जगह अब मल्टियां तन गईं हैं. पेड़ (वट) विकास की भेंट चढ़ गए हैं. ग्रीनरी अब गमलों और बोतलों में सिमट कर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे रही है. लोग अब वृक्षों को देखने जंगल नहीं जाते. अब वे बोन्साई प्लांट देखने एक्जीविशन में जाते हैं. यही कारण है कि आदमी की सोच और दृष्टि भी बोनसाई की तरह निरंतर लघु होती जा रही है. बोनसाई की तरह.

इसी कड़ी में अब अमेरिका से फॉरेन रिटर्न चुनाव चिन्ह, सॉरी इलेक्शन सिंबल तिलचट्टा (कॉकरोच) आया है. वह पढ़ा लिखा और फॉरेन रिटर्न है. सूट और टाई पहनता है. यह सिंबल खूब मशहूर होगा, क्योंकि इसे हमारे घरों में अक्सर रेंगते और दौड़ लगाते हुए अक्सर देखा जाता है. यह ऐसा इलेक्शन सिंबल है कि वोटर इसे भूल नहीं सकता, क्योंकि यदि वोटर इसको भूलने की कोशिश भी करेगा तो यह खुद को भूलने नहीं देगा. कॉकरोच और झाड़ू का बहुत ही करीबी नाता है. यह झाड़ू से ही बुहारा जाता है और उसी में छिप जाता है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि इसका उदगम गंदगी के साथ झाड़ू भी है. देश की राजधानी से झाड़ू गई तो यह नया एडिशन आ गया.

जैसे-जैसे हमारी सियासत, लोकतंत्र, देश और नेता सयाने होते गए वैसे वैसे कृषि से पशुधनों से जुड़े दलों के चुनाव निशान गायब होते चले गए. यह हमारी पशुधन के प्रति उदासीनता का द्योतक बन गया. अब गाय सड़कों पर आवारा घूमतीं हैं और विदेशी डॉग्स घरों में पाले जाते हैं.अब तो राजनीति में हाथ की सफाई है और कीचड़ में खिलने वाला फूल है. गायों की संख्या कम होने का एक कारण यह भी है कि नेताओं की कृपा से चारा, बेचारा हो गया. खुद को गौ पालक होने का दावा करने वाले उनका चारा तक चबा गए और गाय भाई लोगों की भेंट चढ़ गईं. पर्यावरण की ये हालत है कि जब से संस्कृति गंगा जमुनी हो गई तब से न तो गंगा निर्मल बची और न ही जमुना ही पवित्र बची. अब कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो भी थ्री पीस सूट और टाई पहन कर नए कलेवर में हमारे सामने वाया अमेरिका से लाया गया है.इस नई पार्टी को सोशल मीडिया ने जिस तरह हाथों हाथ लिया है उससे कुछ लोगों में सियासी अखाड़े में कूदने की बेताबी लोगों में दिखाई दे रही है. वह उनका विदेशी चीजों के प्रति प्रेम को दर्शाता है. नेता हो या चैन स्नैचर दोनों में एक समानता होती है. ये दोनों चेन छीनते हैं. एक गले से चैन छिनता है और दूसरा जनता के जीवन से चेन छीनता है. स्नैचर को भी सुनहरी धातु के प्रति उतनी ही आसक्ति होती है जितनी सियासतदाओं को होती है.

ट्रेंड, मीम और प्रोपेगेंडा के बीच खोता राष्ट्रबोध

युवाओं की सोच, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित करने वाले डिजिटल नैरेटिव का विश्लेषण

राजेश कुमरावत 'सार्थक'

भारत आज केवल सीमाओं पर ही संघर्ष नहीं लड़ रहा, बल्कि एक अदृश्य वैचारिक युद्ध के दौर से भी गुजर रहा है. यह युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया ट्रेंड, मीम संस्कृति और डिजिटल नैरेटिव के माध्यम से लड़ा जा रहा है. सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस वैचारिक संघर्ष का केंद्र भारत का युवा बनता जा रहा है.

जिस युवा शक्ति को राष्ट्रनिर्माण की ऊर्जा बनना था, उसके सामने धीरे-धीरे ऐसी सामग्री परोसी जा रही है जिसमें राष्ट्रभक्ति उपहास का विषय बनती दिखाई देती है, परंपराओं को पिछड़ेपन से जोड़ा जाता है और सांस्कृतिक चेतना को कट्टरता कहकर प्रस्तुत किया जाता है.

आज सोशल मीडिया पर अचानक उभरने वाले ट्रेंड, व्यंग्यात्मक राजनीतिक प्रयोग, मीम आधारित अभियान और तथाकथित 'डिजिटल क्रांतियाँ' केवल मनोरंजन भर नहीं रह गई हैं.

वे युवाओं की सोच को प्रभावित करने का माध्यम बनती जा रही हैं. हाल के समय में वायरल हुई 'कॉकरोच जनता पार्टी (चट्ठक्क)' जैसी प्रवृत्तियाँ भी इसी व्यापक डिजिटल संस्कृति का हिस्सा प्रतीत होती हैं, जहाँ गंभीर राष्ट्रीय विषयों को व्यंग्य और अराजकता के माध्यम से प्रस्तुत कर युवाओं के भीतर व्यवस्था-विरोधी मानसिकता को आकर्षक रूप दिया जाता है.

लोकतंत्र में आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन जब निरंतर राष्ट्र, आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अविश्वास पैदा करने का वातावरण निर्मित होने लगे, तब यह केवल राजनीतिक असहमति नहीं रह जाती, बल्कि वैचारिक दिशा बदलने का प्रयास दिखाई देने लगता है.

कड़वा सत्य यह भी है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना पर प्रहार हमेशा बाहर से नहीं हुए.कई बार ऐसे विचार देश के भीतर से ही सामने आए जिन्होंने राम, सनातन परंपरा, संतों, राष्ट्रवादी संगठनों और भारतीय इतिहास को संदेह की दृष्टि से देखने का वातावरण बनाया. फिल्मों, मीडिया विमर्शों, विश्वविद्यालयी राजनीति और डिजिटल अभियानों के माध्यम से वर्षों से एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता रहा है जिसमें अपनी जड़ों पर गर्व करने वाला युवा 'पुराना' और अपनी संस्कृति पर प्रश्न उठाने वाला 'प्रगतिशील' कहलाने लगता है.

यही वह मानसिक संघर्ष है जिसे समझना आज आवश्यक है. क्योंकि कोई भी राष्ट्र केवल बाहरी आक्रमणों से कमजोर नहीं होता; वह तब कमजोर होता है जब उसकी नई पीढ़ी अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से भावनात्मक रूप से कटने लगती है.

आज आवश्यकता युवाओं को भड़काने की नहीं, बल्कि उन्हें वैचारिक रूप से जागृत करने की है. उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया का हर ट्रेंड सत्य नहीं होता, हर वायरल नैरेटिव राष्ट्रहित में नहीं होता और हर व्यंग्य प्रगतिशीलता का प्रतीक नहीं होता.

भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी युवा पीढ़ी डिजिटल शोर में अपनी पहचान खोती है या अपनी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रबोध के साथ आधुनिकता का संतुलन बनाती है. क्योंकि जिस दिन भारत का युवा अपनी जड़ों को समझते हुए आगे बढ़ेगा, उस दिन कोई भी प्रोपेगेंडा, ट्रेंड या वैचारिक भ्रम इस राष्ट्र की आत्मा को कमजोर नहीं कर पाएगा.

सार्थक चिंतन : विचारों का संघर्ष हर युग में राष्ट्रों की दिशा तय करता है. राष्ट्र केवल सत्ता से नहीं, बल्कि संस्कृति, चेतना और जागृत समाज से मजबूत बनता है. 'सार्थक चिंतन' उसी राष्ट्रीय विमर्श को शब्द देने का एक प्रयास है.

(लेखक – वरिष्ठ पत्रकार, समसामयिक विश्लेषक एवं भारतीय सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रविचार और डिजिटल सामाजिक प्रवृत्तियों के गंभीर अध्येता हैं.)

बच्चों के स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक का असर

माँ के दूध में पारा और सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक करेंगे भावी पीढ़ी को तबाह?

नीलेश वर्मा

कल तक जो प्लास्टिक हमारी सड़कों और कचरे के ढेरों पर था, आज वहीं प्लास्टिक सब्जियों और रसायन माँ के दूध तक पहुँच चुका है. 2026 की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स चीख-चीख कर गवाही दे रही हैं कि इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए जिस 'प्लास्टिक युग' को जन्म दिया था, अब वही प्लास्टिक हमारी आने वाली पीढ़ियों की साँसों और सेहत को लील रहा है। कल तक जो प्लास्टिक कचरे के ढेरों, नदियों और समुद्रों में तैर रहा था, आज वह अदृश्य होकर हमारी थाली की सब्जियों से होता हुआ खतरनाक रसायन के रूप में माँ के आंचल तक पहुँच चुका है. इसलिए आज सवाल यह है कि माँ के दूध में पारा और सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक भावी पीढ़ी को गंभीर असाध्य रोगों से ग्रसित कर तबाह कर देंगे? साथ ही सुप्रीम कोर्ट के हर घर में गीला, सूखा, खतरनाक और सैनिटरी कचरा अलग-अलग रखने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देशों का पालन होगा?

आज देश के सामने कचरा केवल गंदगी का नहीं, बल्कि शरीर और आने वाली पीढ़ियों के लिए धीमे ज़हर का रूप ले चुका है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हर घर में गीला, सूखा, खतरनाक और सैनिटरी कचरा अलग-अलग रखने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके सख्त पालन की जिम्मेदारी कलेक्टरों व वार्ड पार्षदों को सौपी गई है। क्योंकि प्लास्टिक और जहरीले कचरे का गलत निस्तारण अब मिट्टी, पानी, सब्जियों और इंसानी शरीर तक को प्रदूषित कर रहा है. बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक का असर बीमारियों, हार्मोन गड़बड़ी और बच्चों के स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देने लगा है। भले ही भारत लगभग 60 प्रतिशत प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल कर रहा हो, लेकिन जब तक हर नागरिक अपने घर से प्लास्टिक कम करने और कचरा अलग करने की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तब तक यह संकट कम नहीं होगा। अब यह केवल सफाई का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सवाल बन चुका है।

18 मई 2026 को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि तरक्की की अंधी दौड़ ने माँ के अमृत जैसे दूध को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है. भोपाल में हुई 50 माताओं के दूध की लैब जांच में कुछ सैंपल्स के भीतर पारा (मर्करी) जैसा खतरनाक केमिकल मिला है, जो प्रदूषण या दूषित खान-पान के जरिए महिला के शरीर में जाकर उनके खून और वसा कोशिकाओं (फैट टिश्यूज) में जमा हो जाता है और बाद में दूध के रास्ते सीधे मासूम बच्चे के नाजुक दिमाग और नसों को नुकसान पहुँचाने पहुँच जाता है। इतना ही नहीं, बाजार के जंक फूड के कारण 70 प्रतिशत माताओं के दूध में सोडियम (नमक) का ओवरडोज मिला जो शिशुओं की कच्ची किडनियों के लिए खतरनाक है, जबकि 64 प्रतिशत सैंपल्स में हड्डियों के विकास के लिए जरूरी कैल्शियम की भारी कमी पाई गई।

यही वजह है कि डॉक्टर अब आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए गर्भावस्था और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान पूरी तरह सुरक्षित और प्राकृतिक खान-पान अपनाने की सख्त सलाह दे रहे हैं.

इन रिपोर्टों और आंकड़ों को जान केवल चिंता व्यक्त न करें, बल्कि गंभीरता व जिम्मेदारी के साथ अपनी जीवनशैली बदलें। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को माइक्रोप्लास्टिक और जहरीले प्रदूषण की गिरफ्त से बचाना है तो इसकी शुरुआत हर घर और हर नागरिक को स्वयं करनी होगी। बाजार जाते समय सदैव कपड़े की थैली साथ रखें ताकि प्लास्टिक बैग का प्रयोग कम हो, बच्चों को प्लास्टिक के बजाय स्टील के लंच बॉक्स और धातु की पानी की बोतलें दें, गर्म भोजन को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बों में न रखें तथा रसोई में प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर स्टील, पीतल, कांच या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ाएँ. पूजा सामग्री के चमकीले पाउच, माला, राख और दूषित जल को नदियों-तालाबों में विसर्जित करने की परंपरा पर भी पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि यही प्रदूषण धीरे-धीरे जल, मिट्टी, फसलों और अंततः मानव शरीर तक पहुँचकर नई पीढ़ियों को बीमार बना रहा है। घरों में गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग-अलग रखना अब केवल नियम नहीं, बल्कि भावी संतानों की सुरक्षा का दायित्व है। यदि आज भी समाज ने प्लास्टिक और प्रदूषण के खिलाफ कठोर अनुशासन नहीं अपनाया, तो आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तब हमारी थालियों से लेकर माँ के दूध तक में जहर घुल चुका होगा.

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं.)

हिन्दी पत्रकारिता की दो शताब्दियों की गौरवगाथा

डॉ. अनु श्रीवास्त
प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार
(एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, भोपाल (मप्र)

30 मई भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है. यह वह दिन है जब वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से 'उदन्त मार्तण्ड' नामक प्रथम हिन्दी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था. इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है. यह दिवस केवल एक समाचार पत्र के प्रकाशन की वर्षगांठ नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाई पत्रकारिता की उस समृद्ध परंपरा का उत्सव है जिसने देश की सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

लगभग दो शताब्दियों की यात्रा पूरी कर चुकी हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास संघर्ष, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व का इतिहास है. जिस समय 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन आरंभ हुआ, उस समय अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीय समाज अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा था. संचार के साधन सीमित थे और हिन्दी भाषी समाज तक उसकी अपनी भाषा में समाचार पहुँचाने वाला कोई प्रभावी माध्यम उपलब्ध नहीं था. ऐसे समय में हिन्दी में समाचार पत्र निकालना केवल एक व्यावसायिक निर्णय नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को स्वर देने का साहसिक प्रयास था.

यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 'उदन्त मार्तण्ड' का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, किंतु उसने जिस परंपरा का सूत्रपात किया, वह आगे चलकर भारतीय समाज के बौद्धिक विकास की आधारशिला बन गई. बाद के वर्षों में अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी पत्रकारिता को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं. इन प्रकाशनों ने केवल समाचारों का संप्रेषण नहीं किया, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा प्रसार और राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में हिन्दी पत्रकारिता ने जनजागरण का ऐसा कार्य किया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता. उस समय पत्रकारिता एक मिशन थी. पत्रकार सत्ता से प्रश्न पूछते थे, जनता को जागरूक करते थे और राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक शक्ति प्रदान करते थे. अनेक पत्रकारों ने जेल यात्राएँ कीं, आर्थिक कठिनाइयाँ झेलीं और सरकारी प्रतिबंधों का सामना किया, लेकिन सत्य और राष्ट्रीय हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कमजोर नहीं हुई. वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हिन्दी पत्रकारिता के योगदान के बिना अधूरा है.

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका और व्यापक हुई. लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है और हिन्दी पत्रकारिता ने इस दायित्व का निर्वहन करते हुए शासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य किया. ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक, हिन्दी समाचार पत्रों ने करोड़ों लोगों को सूचना, शिक्षा और जागरूकता प्रदान की. लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक कितने जागरूक हैं, और इस जागरूकता के निर्माण में हिन्दी पत्रकारिता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है.

वर्तमान समय में पत्रकारिता एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है. डिजिटल तकनीक ने सूचना के उत्पादन और प्रसार की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है. इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल पत्रकारिता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने समाचारों की दुनिया को अभूतपूर्व गति प्रदान की है. आज समाचार केवल अखबार के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं. हिन्दी पत्रकारिता ने भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए डिजिटल मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है.

हालाँकि तकनीकी विकास के साथ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं. फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, आधी-अधूरी सूचनाएँ और क्लिक आधारित पत्रकारिता ने मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं. समाचारों की तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच कई बार सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित होती दिखाई देती है. ऐसे समय में पत्रकारिता के मूल सिद्धांत—सत्यता, निष्पक्षता और जनहित—पहले से अधिक प्रासंगिक हो गए हैं.

एक पत्रकारिता शिक्षक के रूप में मैं यह मानती हूँ कि पत्रकारिता का वास्तविक मूल्य उसकी तकनीकी दक्षता में नहीं, बल्कि उसकी नैतिक प्रतिबद्धता में निहित है. पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा प्रदान करना भी है. पत्रकारों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी लेखनी जनमत का निर्माण करती है और लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. इसलिए पत्रकारिता को सनसनी से अधिक सत्य, प्रतिस्पर्धा से अधिक विश्वसनीयता और लाभ से अधिक जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए.

हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है. हिन्दी आज विश्व की प्रमुख भाषाओं में शामिल है और डिजिटल माध्यमों पर हिन्दी सामग्री की मांग लगातार बढ़ रही है. यह अवसर हिन्दी पत्रकारिता को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकता है. आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी गौरवशाली परंपरा से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक तकनीक और पत्रकारिता मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखें.